(ग) राज्यों के अन्दर छोटे सम्पर्क

(घ) ऐसे अन्तरण जिनमें दो राज्य सम्मिलित हों

(ङ) ऐसे अन्तरण जिनमें दो से अधिक राज्य और अन्तर्राष्ट्रीय नदियां शामिल हों ।

15. आगे अन्वेषण प्रारम्भ करने से पहले प्रारम्भिक अध्ययनों पर आधारित राजनैतिक सहमति पर पहुंचने की आवश्यकता को पूर्वापेक्षित समझा गया ।

आदिवासी क्षेत्रों में फलोद्यान लगाया जाना

*199. श्री अजीत जोगी :
श्री राधाकिशन मालवीय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फलोद्यान विकास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में किसानों को फलोद्यान लगाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कोई शेष प्रयास किए जाने का प्रस्ताव है ताकि इन क्षेत्रों के गरीब आदिवासी किसानों को लाभ पहुंचे सके, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है,

(ख) मध्य प्रदेश के ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहां वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं से आदिवासियों को लाभ पहुंचा है तथा इनसे कितने आदिवासियों को कितना लाभ पहुंचा है, और

(ग) इस संदर्भ में आगामी वर्षों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने मध्य प्रदेश में बागवानी के विकास की क्षमता के बारे में एक अध्ययन किया है । इस अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2025 तक बस्तर, रायगढ और सरगुजा नामक आदिवासी जिलों में फलोद्यान के अंतर्गत 2,85,000 हैक्टेयर का विकास करना संभव होगा ।

(ख) केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत बस्तर में अन्नानास तथा काजू की खेती के लिए सहायता दी गई है ।

राज्य सरकार आदिवासी जिलों में निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है :

(1) शाहदोल, सरगुजा, बेतुल, बिलासपुर, होशंगाबाद, बस्तर, धाड़ और रायगढ नामक जिलों में फल रोपण राजसहायता योजना ।

(2) आदिवासी जिलों में कार्यान्वित की जा रही आदिवासी योज्य योजना के अंतर्गत सामुदायिक फलोद्यानों का विकास ।

(3) जवाहर रोजगार योजना—बस्तर, रायगढ तथा सरगुजा नामक आदिवासी जिलों में फल रोपण से संबंधित कार्यकलाप।

उपयुक्त योजनाओं से लगभग 5000 आदिवासियों को लाभ मिल रहा है ।

(ग) केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत 5 वर्षों में 400 हैक्टेयर (अन्नानास द्वारा) कवर करने तथा प्रति वर्ष 100 हैक्टेयर (काजू द्वारा) कवर करने की सम्भावना है ।

1992–93 में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 2100 हैक्टेयर तथा फल रोपण राजसहायता योजना के अंतर्गत 650 हैक्टेयर क्षेत्र कवर करने का लक्ष्य रखा गया है ।

Setting up of an aluminium plant in Orissa

*200. SHRI BASANT KUMAR DAS: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether the Government of Orissa has sent a proposal for setting up an aluminium plant in the State;